

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(ए. डी. सरकारी को. उद्योग)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

महाप्रबन्धक (औस) e-mail-ashok.agnihotri@yahoo.com

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं० : 1947- औस एवं विनियम / पाकालि / 2010-13-विनियम/86

दिनांक : 5.08.2010

कार्यालय-ज्ञाप

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् की विज्ञप्ति सं० 8082-जी०/राविप-2-169ए/1970 दिनांक 18.10.75 (समय-समय पर संशोधित) द्वारा अपने कार्मिकों (अधिकारियों/कर्मचारियों) की सेवा-शर्तों के नियमन हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तों), विनियमावली, 1975 का सृजन किया गया। उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तों), विनियमावली, 1975 सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में भी प्रभावी है।

2. उक्त उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तों), विनियमावली, 1975 के विनियम-06 में पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त आरोपो/शिकायतो आदि की जाँच हेतु एक या अधिक, जैसा वे आवश्यक समझे, जाँच समिति(यों) गठित किये जाने का प्राविधान है। पूर्ववर्ती परिषद् द्वारा उक्त विनियम-06 में प्राप्त अधिकारों के प्रयोग में जाँच समिति-1 व जाँच समिति-11 का गठन किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत है।

3. उ०प्र० शासन द्वारा विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उ०प्र० विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (जिसे आगे कारपोरेशन कहा जायेगा) एवं इनकी सहयोगी विद्युत वितरण निगमों (यथा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, कानपुर) (जिसे आगे विद्युत वितरण निगम कहा जायेगा)/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० (जिसे आगे ट्रास्को कहा जायेगा) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्मिकों में अनुशासन बनाये रखने के लिये यह आवश्यक समझा जा रहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त आरोपो, शिकायतो अथवा दोषों की जाँच हेतु विद्यमान व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।

4. उक्त प्रस्तर-3 में इंगित तथ्यों को दृष्टिगत कर उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) (सेवा की शर्तों), विनियमावली, 1975 के वर्तमान विनियम-06 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है

:-

अ.

वर्तमान विनियम-06	प्रतिस्थापित विनियम-06
" Constitution of committee to inquire into Cases :- 3- The Board may from time to time constitute one or more enquiry committees, as it may consider necessary for inquiry into allegations, complaints or charges against officers and servants.	प्रकरणों की जाँच हेतु समिति का गठन :- 1. कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं विद्युत वितरण निगमों तथा ट्रास्को के प्रबन्ध निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे अपने कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) से सम्बन्धित आरोपो/शिकायतो की जाँच हेतु आवश्यकतानुसार एक या अधिक जाँच समिति(यों) का गठन कर सकें, 2. कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे कारपोरेशन अथवा विद्युत वितरण निगमों अथवा ट्रास्को के कार्मिकों (अधिकारियों एवं कर्मचारियों)



कू० प० 3०

4- Every Enquiry Committee constituted under clause (1) shall consist of the following :- (i) A Chief Engineer or Additional Chief Engineer, UPSEB (ii) A Law Officer or Additional Law Officer, UPSEB (Member) (iii) An Officer from the Accounts Branch of UPSEB not below the rank of Accounts Officer nominated by the Chairman in that Behalf (Member) "	से सम्बन्धित आरोपों/शिकायतों की जाँच कारपोरेशन अथवा उक्त प्रस्तर-1 में इंगित प्रबन्ध निदेशको द्वारा गठित किसी भी जाँच समिति को सन्दर्भित कर सके, 3. उक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत गठित प्रत्येक जाँच समिति में निम्न होंगे :- अ. एक मुख्य अभियन्ता _____ संयोजक ब. लेखा शाखा का एक अधिकारी (जो लेखाधिकारी से कनिष्ठ स्तर का न हो) _____ सदस्य 4. उक्त प्रस्तर-3 में गठित जाँच समिति के संयोजक को यह अधिकार होगा कि वे किसी प्रकरण पर विधि अथवा किसी अन्य विधा के कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम/ट्रास्को में तैनात विशेषज्ञ की सेवाएँ किसी भी रूप में जाँच की किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सके, 5. जाँच समिति द्वारा प्राप्त प्रकरणों की जाँच में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा :- क. जाँच समिति प्रकरण प्राप्त होने के अधिकतम पैंतालिस दिन में आरोप-पत्र सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध करायेगी, ख. जाँच समिति सम्बन्धित कार्मिक से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने के तीस दिन में सुनवाई प्रारम्भ कर देगी जो अधिकतम पैंतालिस दिन में पूरी कर ली जायेगी, ग. जाँच समिति द्वारा सुनवाई पूर्ण होने के अधिकतम पैंतालिस दिन में जाँच आख्या सम्बन्धित कारपोरेशन के निदेशक (का0प्रब0एवंप्रशा0) अथवा प्रबन्ध निदेशक को उपलब्ध करायेगी, घ. कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0) एवं निगमों/ट्रास्को के प्रबन्ध निदेशक जाँच समिति से आख्या प्राप्त होने के पैंतालिस दिन में जाँच आख्या का परीक्षण कर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करेंगे, य. जाँच समिति उक्त प्रस्तर क से घ में इंगित समय-सीमा का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में कारपोरेशन/सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को इनके कारणों/परिस्थितियों से अवगत करायेगे एवं इनका उल्लेख जाँच आख्या में करेंगे।
---	--

ब. उक्त संशोधित प्राविधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अर्थात्, जिन प्रकरणों में सुनवाई आदि की कार्यवाही पूर्व प्राविधानों के अनुसार की गई है, उनमें जाँच आख्या पूर्व प्राविधानों के अनुसार ही कारपोरेशन के निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0) को उपलब्ध कराई जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पृ० सं० 1947 (1)- औस एवं विनियम / पाकालि / 2010-13-विनियम/86 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

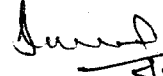
(1) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(2) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।



(3)

- (3) अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा० ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
- (5) समस्त निदेशक गण, उ०प्र०पा०का०लि० के निजी सचिव।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/ केस्को, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।
- (7) मुख्य अभियन्ता एवं संयोजक, जॉय समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- (8) महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशा०)/महाप्रबन्धक (औस)/अपर विधि अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (9) अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अरा०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (10) कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को उनके पत्रांक 692-पाकालि/बैठक (84)/2010 दिनांक 28.07.2010 की मद सं० चौरासी (52)/10 के सन्दर्भ में।
- (11) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।


(जावेद अहमद) 28/7/10
अनुसचिव (विनियम)